संपादकीय जागरण

मंगलवार, 3 जुलाई, 2018 : आषाढ़ कृष्ण 5 वि. 2075

आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है

अफगानिस्तान में अनर्थ

अफगानिस्तान के प्रमुख शहर जलालाबाद में सिखों और हिंदुओं को निशाना बनाकर किए गए भीषण आतंकी हमले में करीब 20 लोगों की मौत पर भारत सरकार ने उचित ही चिंता प्रकट की, लेकिन यह भी साफ है कि केवल इतने भर से बात बनने वाली नहीं है। इस हमले के बाद भारत सरकार को कहीं अधिक सक्रियता दिखाने की जरूरत है, क्योंकि जलालाबाद और आसपास के इलाके में रह रहे बचे-खुचे सिख अब खुद को सुरक्षित नहीं मान रहे हैं। अगर वे पलायन के लिए विवश होते हैं तो फिर अफगानिस्तान के दूसरे हिस्सों में रहने वाले सिख और अन्य अल्पसंख्यक अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो सकते हैं। यह चिंता उन्हें भी अफगानिस्तान छोड़ने के लिए मजबूर कर सकती है। अफगानिस्तान में रह रहे सिखों और हिंदुओं के साथ अन्य अल्पसंख्यकों की जिंदगी कितनी जोखिम भरी है, यह इससे समझा जा सकता है कि करीब दो दशक पहले उनकी संख्या एक लाख से अधिक थी, लेकिन आज वे बमुश्किल दो-चार हजार ही बचे हैं। अतीत में तालिबान की बर्बरता का सामना कर चुके अफगानिस्तान के सिखों और हिंदुओं पर ताजा हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट यानी आइएस नामक संगठन ने ली है, लेकिन इस बारे में कुछ कहना कठिन है कि यह किसकी हरकत है? हैरत नहीं कि आइएस के नाम का उल्लेख केवल सनसनी पैदा करने अथवा प्रचार पाने के लिए किया गया हो और यह काम अंजाम दिया हो किसी तालिबानी गुट ने। इसकी आशंका इसलिए भी है, क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान समेत अन्य अनेक देशों में सक्रिय किस्म-किस्म के आतंकी संगठनों में खुद को आइएस से जुड़ा हुआ बताने का सिलसिला तेज हो गया है।

जलालाबाद में सिखों और हिंदुओं को आत्मघाती हमले का शिकार बनाने का काम चाहे जिस आतंकी समूह ने किया हो, यह साफ है कि उसका मकसद अफगानिस्तान सरकार के साथ-साथ भारत सरकार को भी कोई संदेश देना था। कहीं इस आतंकी गुट ने सिखों और हिंदुओं को निशाना बनाने का काम पाकिस्तान के इशारे पर तो नहीं किया? यह सवाल इसलिए, क्योंकि अफगानिस्तान के उत्थान में भारत के हाथ बंटाने से यदि किसी को परेशानी है तो वह पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में भारत की सक्रियता इसलिए रास नहीं आ रही, क्योंकि वह काबुल में अपनी कठपुतली सरकार चाहता है और उसे लगता है कि भारत इसमें बाधक है। पाकिस्तान की इस सोच के पीछे एक बड़ी वजह अफगानिस्तान को अपनी जागीर के तौर पर देखना है। यदि पाकिस्तान की पहली सनक भारत को नीचा दिखाना है तो दूसरी सनक अफगानिस्तान को अपने नियंत्रण में देखना। इसी कारण वह तालिबान सरीखे खूंखार तत्वों को अपना सहयोग, समर्थन और संरक्षण दे रहा है। चूंकि जलालाबाद हमले में मारे गए सिख और हिंदू अफगानिस्तान के राष्ट्रपति से मिलने जा रहे थे इसलिए उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दोषी बचने न पाएं। निःसंदेह यह भी अपेक्षित है कि अमेरिका और साथ ही अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर चिंतित अन्य देश भी जलालाबाद की आतंकी घटना का संज्ञान लें। इन सभी देशों को यह भी देखना चाहिए कि कहीं पाकिस्तान आतंक का नए सिरे निर्यात तो नहीं कर रहा है?

संकल्प भी जरूरी

निरंतर अभियान चलाने के बावजूद गांव अभी भी खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) नहीं हो सके हैं। हालांकि गांवों में स्वच्छता अभियान की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब जिलाधिकारियों को गांधी जयंती (दो अक्टूबर) तक राज्य को खुले में शौच से मुक्ति (ओडीएफ) दिलाने का लक्ष्य दिया है। शुरू में कुछ जिलों, गांव और ग्राम पंचायतों ने काफी तेजी भी दिखाई, कई जिलों के ब्लाक और गांवों को ओडीएफ घोषित भी कर दिया गया, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही निकली। कहीं शौचालय अधूरे थे, तो कहीं मानक के अनुरूप नहीं थे। कहीं बन भी गए तो लोग उनका इस्तेमाल करने से कतराते दिखे। ऐसी और भी कई समस्याएं देखने में आईं।

> लक्ष्य पूरा करने के लिए अब भी तीन माह का वक्त है। यदि सरकारी मशीनरी और आम जनता दोनों ही ठान लें तो लक्ष्य हासिल करना मुश्किल नहीं है

बड़ी बात तो यही थी कि गरीब और समर्थ दोनों ही तरह के लोग सरकारी खर्च पर ही शौचालय बनाने की बाट जोहते रहे। शौचालय निर्माण में भ्रष्टाचार और अनियमितता भी सामने आई। हालांकि इस मामले में फीरोजाबाद की सीडीओ ने जरूर उदाहरण प्रस्तुत किया। वस्तुतः ऐसी ही जिम्मेदारी का भाव सभी संबंधित अधिकारियों को दिखाना पड़ेगा। आम जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। सरकार पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय समर्थ लोगों द्वारा अपने खर्च पर शौचालय का निर्माण कराना चाहिए। लक्ष्य पूरा करने के लिए तीन माह हैं। यदि सरकारी मशीनरी और जनता दोनों ही ठान लें तो लक्ष्य हासिल करना मुश्किल नहीं है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या बीते एक साल में जीएसटी का कार्यान्वयन सुगम रहा है?

आज का सवाल

क्या पूर्ण राज्य के दर्जे के बिना दिल्ली का विकास संभव नहीं है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y –हां, **N**–नहीं, **C**–कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।
सभी आंकड़े प्रतिशत में।

दोहरे फायदे वाला ट्रेड वार

डॉ. भरत झुनझुनवाला

आयात शुल्क बढ़ने से जहां घरेलू उद्यमों को सहारा मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे वहीं सरकारी राजस्व में इजाफे से कल्याणकारी योजनाओं पर भी खर्च बढ़ेगा

अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री लैरी समर्स ने कहा है कि अमेरिका और चीन के बीच मंडरा रहे ट्रेड वार के कारण वैश्विक मंदी आ सकती है। हाल के दौर में अमेरिका ने चीन से आयातित माल पर आयात शुल्क बढ़ा दिए और इसकी प्रतिक्रिया में चीन ने भी यही करते हुए अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क में इजाफा कर दिया। आयात कर बढ़ाने से घरेलू बाजार में आयातित माल के दाम बढ़ जाते हैं। जैसे अमेरिका में चीन में निर्मित फुटबॉल का आयात हो रहा था तो उस पर अमेरिका ने आयात कर बढ़ा दिया। इससे अमेरिका में वह फुटबॉल महंगी हो जाएगी। समर्स जैसे कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस प्रकार के ट्रेड वार से उद्यमियों और उपभोक्ता दोनों का आत्मविश्वास कम होगा और वैश्विक मंदी आ सकती है। इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार, प्रथम चरण में अमेरिका द्वारा आयात कर बढ़ाने से कच्चा एवं आयातित माल महंगा हो जाएगा। इससे अमेरिकी उपभोक्ता को उसी माल को खरीदने में अधिक मूल्य अदा करना पड़ेगा। उसकी क्रय शक्ति घटेगी। परिणामस्वरूप बाजार में कुल मांग घटेगी। कच्चा माल महंगा होने से अमेरिकी कंपनियों के लिए माल का उत्पादन करना कठिन हो जाएगा। इसके बाद चीन द्वारा प्रतिक्रिया में अमेरिकी माल पर आयात कर बढ़ाने से एप्पल जैसी अमेरिकी कंपनियों के लिए चीन को माल का निर्यात करना कठिन हो जाएगा। एप्पल द्वारा अमेरिका में निवेश और रोजगार दोनों का हनन होगा। तीसरे बिंदु पर अमेरिकी उद्यमियों एवं उपभोक्ताओं का आत्मविश्वास कम होगा और वे कोमा में चले जाएंगे। इससे कुल मिलाकर वैश्विक मंदी की आशंकाएं ही बढ़ेंगी। अब इस घटनाक्रम की दूसरी संभावना पर विचार करें। अमेरिका में आयातित माल महंगा होने से घरेलू उद्यम की गाड़ी भी जोर पकड़ सकती है। जैसे चीन में बनी फुटबॉल पर अमेरिका में आयात कर अधिक लगने से वे अमेरिका में महंगी हो जाएंगी, लेकिन अमेरिका में फुटबॉल बनाने वाली इकाई के कारोबार में तेजी आएगी। अमेरिका में उत्पादित फुटबॉल के दाम अवश्य ऊंचे होंगे, परंतु अमेरिका में फुटबॉल बनाने वाली कंपनी में निवेश बढ़ेगा। इससे रोजगार के अवसरों में भी इजाफा होगा।

घटनाक्रम के दूसरे बिंदु पर यह सही है कि चीन द्वारा प्रतिक्रिया में अमेरिकी माल पर आयात कर बढ़ाने से अमेरिका द्वारा एप्पल फोन जैसे माल का निर्यात कम होगा, लेकिन अमेरिका द्वारा चीन से माल आयात अधिक किया जा रहा है और निर्यात कम किया जा रहा है। परिणामस्वरूप अमेरिका के निर्यातकों को नुकसान कम होगा, क्योंकि निर्यात वैसे ही कम है। इसकी तुलना में आयात कम होने से लाभ अधिक होगा, क्योंकि आयात अधिक हैं। चीन के साथ माल का व्यापार कम होने से अमेरिका को लाभ होगा। घटनाक्रम का तीसरा बिंदु है कि समर्स जैसे अर्थशास्त्रियों के अनुसार अमेरिकी कंपनियों और उपभोक्ताओं का विश्वास कम होगा, क्योंकि उन्हें महंगा माल खरीदना होगा, लेकिन मेरे आकलन में अमेरिकी कंपनियों का आत्मविश्वास बढ़ सकता है, क्योंकि वहां फुटबॉल की फैक्ट्रियां लगाने का अवसर मिलेगा। अमेरिकी उपभोक्ताओं का भी आत्मविश्वास बढ़ सकता है, क्योंकि उन्हें फुटबॉल कारखानों में रोजगार मिलेंगे। ट्रंप वास्तव में अमेरिकी जनता की परिस्थिति को समझ रहे हैं और उन्होंने एक सोची समझी रणनीति के तहत ही यह ट्रेड वार शुरू किया है जिससे अमेरिका को फायदा होने की उम्मीद है।

अवधेश राजपूत

प्रश्न है कि फिर तमाम अर्थशास्त्रियों द्वारा ट्रेड वार के कारण वैश्विक मंदी की बात को क्यों कहा जा रहा है? मेरा मानना है कि ट्रेड वार उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए नुकसानदेह होगा जिन्होंने चीन में फैक्ट्रियां लगा रखी हैं। इनका चीन में धंधा चौपट हो जाएगा। यह ट्रेड वार चीन के लिए भी नुकसानदेह होगा। अमेरिका में फुटबॉल पर आयात कर बढ़ाने से अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए चीन में निवेश करने के अवसर कम होंगे और चीन में भी मंदी आ सकती है। इससे चीन में रोजगार भी घटेंगे। अब इस घटनाक्रम का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देखें। ट्रेड वार का अमेरिका पर सुप्रभाव पड़ेगा जबकि चीन पर कुप्रभाव। दोनों जोड़ देंगे तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव शून्यप्राय होगा। अंतर यह होगा कि जो रोजगार एवं उत्पादन आज चीन में हो रहा है वह आने वाले समय में अमेरिका को स्थानांतरित हो जाएंगे।

ट्रेड वार के वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का एक और पक्ष है। सामान्य रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा माल ऑटोमेटिक मशीनों द्वारा उत्पादित किया जाता है जबकि छोटे घरेलू उद्यमों द्वारा इसमें श्रम का उपयोग ज्यादा होता है। इससे रोजगार ज्यादा बनते हैं। जाहिर है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सिकुड़ने एवं घरेलू कंपनियों के बढ़ने से कुल रोजगार बढ़ेंगे। नकारात्मक प्रभाव यह होगा कि वैश्विक स्तर पर माल के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि अमेरिका में उत्पादित फुटबॉल महंगी होगी, लेकिन मेरे आकलन में माल का महंगा होना जनता को फिर भी स्वीकार हो सकता है, क्योंकि उसकी पहली मांग रोजगार की होती है। रोजगार के सामने महंगे माल का कुप्रभाव कम होगा। इस प्रकार वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए यह ट्रेड वार नुकसानदेह नहीं, बल्कि लाभदायक होगा। ट्रेड वार का एक और सकारात्मक पहलू यह है कि अमेरिका में आयातित माल पर आयात कर बढ़ा देने से अमेरिकी सरकार को राजस्व मिलेगा जिसका उपयोग कल्याणकारी योजनाओं में किया जा सकता है। इस प्रकार आम आदमी को ट्रेड वार से दोहरा लाभ हो सकता है। रोजगार बढ़ेंगे और सरकारी कल्याणकारी योजनाएं भी बढ़ेंगी। साथ ही साथ खरीद का दाम भी बढ़ेगा। खरीद के दाम बढ़ने से हुए नुकसान की तुलना में रोजगार और कल्याणकारी योजनाओं से लाभ अधिक होगा। इस प्रकार यह ट्रेड वार जनता के लिए अच्छा है।

भारत की परिस्थिति मूल रूप से अमेरिका के समान है। अमेरिका की तरह भारत भी आयात ज्यादा करता है। इसलिए ट्रेड वार भारत के लिए भी लाभकारी होगा। हमारे द्वारा आयात कर बढ़ाने से आयात में भारी गिरावट आएगी, जबकि चीन और अमेरिका द्वारा हमारे निर्यात पर आयात कर बढ़ने से गिरावट कम आएगी। इसलिए यह ट्रेड वार भारत के लिए भी लाभकारी होगा। इस परिप्रेक्ष्य में हमें अमेरिका द्वारा भारतीय स्टील एवं एल्युमीनियम पर हाल में बढ़ाए गए आयात कर को समझना चाहिए। अमेरिका का यह कदम हमारे लिए एक सुनहरा अवसर था। हम ट्रेड वार की आग में घी डाल सकते थे। यदि हम अमेरिकी आयात के साथ ही चीनी आयात पर भी आयात कर बढ़ाते तो अपने देश में भी फैक्ट्रियां लगने लगतीं और रोजगार भी बनते। हां हमें सस्ता चीनी माल उपलब्ध नही होता, लेकिन रोजगार के सुख के सामने महंगे माल का कष्ट बहुत कम होता है। भारत को प्रतिक्रिया में अमेरिका के साथ चीन से आयातित माल पर आयात कर बढ़ा देने चाहिए और घरेलू उद्यम तथा उपभोक्ता के हित साधने चाहिए।

(लेखक वरिष्ठ अर्थशास्त्री एवं आइआइएम बेंगलुरु के पूर्व प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

आर्थिक एकता का सूत्र जीएसटी

सुशील कुमार मोदी

जीएसटी के जरिये हमें 'एक देश-अनेक कर' से 'एक देश-एक कर' की दिशा में बढ़ने में सहायता मिली है

वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी प्रणाली लागू हुए एक साल पूरा हो गया। इस टैक्स प्रणाली से पहले अपने देश में अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था काफी अराजक स्थिति में थी। वस्तुतः तब एक देश-अनेक कर का दौर था। सरदार पटेल की ओर से किए गए देश के राजनीतिक एकीकरण के पहले देश में जैसा राजनीतिक परिवेश था कुछ वैसी ही स्थिति अप्रत्यक्ष करों के मोर्चे पर भी थी। जीएसटी से पहले की टैक्स प्रणाली की विसंगतियां देश के आर्थिक एकीकरण में बड़ी बाधा बनी हुई थीं। आर्थिक एकीकरण के लिए यह आवश्यक था कि संविधान की आठ प्रकार की प्रविष्टियों के अधीन 37 अलग-अलग कर प्रशासनों द्वारा लगाए जा रहे 16 तरह के टैक्स और 15 तरह के सेस यानी अधिभार एक सूत्र में पिरोए जाएं। अधिभार हेतु एकल आधारित व्यवस्था और एकीकृत टैक्स प्रशासन का ढांचा तैयार किया जाए। इस दिशा में पहला महत्वपूर्ण कार्य संविधान में संशोधन का था। अगली चुनौती जीएसटी लागू किए जाने और उसके लिए एक समान कानून एवं अनुपालन के लिए नियम तैयार करने की थी। इसके अतिरिक्त एक और चुनौती सुदृढ़ सूचना प्रौद्योगिकी आधारित पोर्टल के निर्माण की भी थी जो संभवतः विश्व के सबसे बड़े कर प्रशासन का तंत्र बनता और जिस पर सभी राज्यों को एक साथ एक मंच पर लाया जा सके।

जीएसटी प्रणाली लागू होने पर तकनीकी कारणों से शुरुआती एक महीने में कई समस्याएं आईं, परंतु जीएसटी काउंसिल द्वारा नियमित अंतराल पर की गई बैठकों के द्वारा उनका उचित समाधान भी तलाशा गया। जीएसटी काउंसिल के अथक प्रयासों से आज देश में यह टैक्स प्रणाली स्थिरता की ओर अग्रसर है। भारत में जीएसटी लागू करने की प्रक्रिया का संभवतः सबसे सकारात्मक पहलू यह है कि अपनी बैठकों में काउंसिल ने कंपोजीशन की सीमा में बढ़ोतरी जैसे छोटे से छोटे मसले से लेकर राज्य और केंद्र के बीच क्षेत्राधिकार बंटवारे जैसे गंभीर विषयों पर भी सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए और किसी भी मामले में राज्यों अथवा केंद्र को मत प्रयोग करने की नौबत नहीं आई। यह अपने आप में राज्यों की राजनीतिक परिपक्वता एवं केंद्रीय वित्त मंत्री की कार्यकुशलता का परिचायक है। राजस्व प्राप्ति की स्थिति काफी उत्साहवर्धक रही है। जीएसटी लागू होने के बाद पहले आठ महीनों में यानी मार्च 2018 तक कुल 7.41 लाख करोड़ रुपये का राजस्व मिला। औसत मासिक आधार पर यह राशि 92,491 करोड़ रुपये बैठती है। इस आधार पर वार्षिक कर राजस्व 11.11 लाख करोड़ रुपये बनता है। यह वर्ष 2015-16 की तुलना में लगभग 12 प्रतिशत की वृद्धि रेखांकित करता है। जीएसटी के तहत केंद्र द्वारा राज्यों को 14 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर के आधार पर राजस्व देने की गारंटी दी गई है। हालांकि केंद्र के पास ऐसी कोई राजस्व सुरक्षा नहीं है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि यह वृद्धि दर ऐसी स्थिति में प्राप्त की जा सकी है जब क्रेडिट के दावों के सत्यापन की कोई ठोस व्यवस्था तैयार नहीं हो सकी थी और न ही ई-वे बिल की जांच प्रभावी ढंग से हो पा रही है। यद्यपि अप्रैल, 2018 से लागू ई-वे बिल की व्यवस्था अभी भी अपने प्रायोगिक चरण में ही है, फिर भी पिछले महीने का राजस्व संग्रह 94,000 करोड़ रुपये के स्तर को पार कर गया है। हमें उम्मीद है कि क्रेडिट दावों के सत्यापन की समुचित व्यवस्था लागू होने और ई-वे बिल प्रणाली व्यवस्थित रूप से मूर्त रूप लेने पर राजस्व प्राप्ति में व्यापक सुधार दिखेगा। तब तक इसके सरलीकरण की प्रक्रिया जारी रहेगी। जीएसटी के मूल ढांचे में सुधार के क्रम में पेट्रोलियम पदार्थों और रियल एस्टेट को जीएसटी के दायरे में लाए जाने और टैक्स की दरों को तार्किक बनाने पर मंथन हो सकता है। मेरे ख्याल से अभी इन मुद्दों पर जल्दबाजी में कोई कदम उठाया जाना उचित नहीं होगा।

पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने में कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि पेट्रोलियम उत्पाद केंद्र और राज्यों के लिए राजस्व का प्रमुख स्रोत हैं और इस मुद्दे पर राज्यों की सहमति प्राप्त करना आसान नहीं। जीएसटी के दायरे में लाए जाने मात्र से पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों पर कोई बड़ा असर पड़ना तय नहीं है, क्योंकि अपने राजस्व को संरक्षित रखने के लिए राज्यों और केंद्र द्वारा पेट्रो उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने की प्रबल संभावना है। पेट्रोलियम उत्पादों के मामले में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यही परिपाटी है। रियल एस्टेट भी राज्यों के राजस्व का एक स्थिर स्रोत है और इसे जीएसटी में शामिल करने को लेकर राज्य कुछ सशंकित हैं। हालांकि मेरा यह मानना है कि इसे जीएसटी के दायरे में लाने से इस क्षेत्र की विसंगतियां दूर होकर यह और पारदर्शी बन जाएगा।

राजस्व में स्थिरता की स्थिति दिखने पर टैक्स दरों को और तर्कसंगत बनाए जाने के लिए उनमें कमी किए जाने पर विचार किया जा सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण होगा टैक्स दर ढांचे में सुधार पर विचार करना। 28 प्रतिशत की अधिकतम दर वाली श्रेणी में केवल विलासिता, पर्यावरण को दूषित करने वाली वस्तुएं रखी जा सकती हैं। इसी तरह दो दर श्रेणियों के विलय पर भी विचार हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण है विवरणियों का सरलीकरण और विवरणी दाखिल की प्रक्रिया को सरल बनाना। यह प्रक्रिया इतनी सरल होनी चाहिए जिससे विवरणी न्यूनतम आवश्यक सूचना और कम से कम परेशानी से दाखिल की जा सके-ठीक वैसे ही जैसे मधुमक्खी फूलों को न्यूनतम क्षति पहुंचाते हुए परागकण ले लेती है। संग्रहित आइजीएसटी का और भी त्वरित गति से बंटवारा भी एक गंभीर चुनौती है। इसमें विलंब का मुख्य कारण जीएसटीआर-2 विवरण को दाखिल करने में दिया गया अवधि विस्तार भी है। हमें इससे इतर कोई और सशक्त तरीका खोजना पड़ेगा ताकि बंटवारा समय से हो सके। इस संदर्भ में इस बात का उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि यद्यपि गंतव्य आधारित टैक्स व्यवस्था होने के कारण बिहार जैसे राज्यों को काफी लाभ मिलने की संभावना थी, लेकिन आइजीएसटी राशि के जमा होने और समय पर बंटवारा नहीं होने के कारण आज यह राज्य भी राजस्व हानि की समस्या से ग्रस्त हो गया है। आइजीएसटी के नियमित और ससमय बंटवारे से जहां एक ओर राज्यों को उनका यथोचित अंश मिल सकेगा वहीं इससे केंद्र का राजकोषीय बोझ भी हल्का होगा। जीएसटी के जरिये हमें 'एक देश-अनेक कर' से 'एक देश-एक कर' की दिशा में बढ़ने में मदद मिली है। यह सहकारी संघवाद की दिशा में एक सराहनीय अध्याय है। इसने राष्ट्र की राजनीतिक एकता एवं अखंडता के साथ देश को एक समेकित बाजार के रूप में परिवर्तित करते हुए आर्थिक एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया है।

(लेखक बिहार के उप-मुख्यमंत्री एवं जीएसटीएन पर बने मंत्री समूह के प्रमुख हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

कर्तव्य

परिस्थितियां कैसी भी विषम क्यों न हों, राह पर चलते जाना ही धर्म है। गुण स्वभाव का अंग हो जाते हैं तभी उन्हें गुण कहा जाता है। स्थितियों के अनुसार उन्हें अपनाना या त्याग देना सबसे बड़ा अवगुण है। शीतलता चंदन का गुण है, जो हर हाल में बना रहता है। चंदन के पेड़ पर कितने ही विषैले सांप लिपटे हों, उसकी शीतलता बनी रहती है। यदि एक वृक्ष अपने गुणों पर इस तरह दृढ़ रह सकता है तो मनुष्य क्यों नहीं, जिसे ईश्वर ने बौद्धिक चेतना प्रदान कर उसे जीवों में विशिष्ट बना दिया है। कदाचित मनुष्य ही इसे समझ नहीं पा रहा है कि विचार और आचार की शुद्धता ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य और उपलब्धि है।

दया, परोपकार, क्षमा, दान और साहचर्य जैसे तत्व मनुष्य की रचना में ही समाहित हैं और उन पांच तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनसे यह तन बना है। इनसे विरत होना अपने संरचनात्मक स्वभाव से दूर जाना है। भूमि, जल, वायु, अग्नि और क्षितिज एक साथ बने रहते हैं तो सृष्टि का अस्तित्व है और मनुष्य का भी। इनका असंतुलन यदि सृष्टि को विनाश की ओर ले जाने वाला है तो मनुष्य को भी। जीवन में तमाम विषधारी समस्याओं से सामना होता रहता है। मनुष्य का धर्म है कि सहज रहकर अपने गुणों से उनसे पार पाने की चेष्टा करे।

किसी का भी जीवन कभी भी निष्कंटक नहीं रहा है। संसार में जो महापुरुष हुए हैं, उन्होंने भी असीम दुख सहे। उनके मार्ग में रोंगटे खड़े कर देने वाली बाधाएं आईं, किंतु वे अविजित रहे तो अपने सद्गुणों के कारण। इसीलिए आज उनकी पूजा होती है। उनकी उपलब्धियों को संसार ने याद रखा है। जीवन में सुख नहीं रहते तो दुख भी टल जाते हैं। वास्तव में सुख और दुख की अवधारणा ही दोषपूर्ण है। मनुष्य कर्मों की पूंजी एकत्र करता चले तो वह सुख और दुख से ऊपर उठ जाता है और निर्लिप्त अवस्था प्राप्त कर लेता है। मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलना है। यदि बबूल बोया है तो अंगूर कहां से मिलेंगे। अंगूर पाने के लिए अंगूर की ही खेती करनी पड़ेगी। मात्र अपने कर्म करते जाने में ही उसे असीम आनंद मिलता है। जिन कार्यों से आत्म संतुष्टि मिले, वे ही सद्कर्म हैं और सद्गुणों के प्रतीक हैं। इनसे ही जीवन का प्रवाह बना रहता है और इसी से ही उसकी अविरल धारा बनाई रखी जा सकती है।

डॉ. सत्येंद्र पाल सिंह

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

प्रकृति से खिलवाड़

शहरी विकास का बदरंग चेहरा शीर्षक से लिखे अपने लेख में हृदयनारायण दीक्षित ने भौतिकतावाद की अंधी दौड़ में प्रकृति से खिलवाड़ को प्राणी जाति के लिए घातक बताया है। महात्मा गांधी ने कहा था कि भोग की बढ़ती प्रवृत्ति ही प्रकृति का दोहन करवाती है इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। जल, जमीन और भोजन जैसी अनिवार्य सुविधाओं के लिए हमें प्रकृति का दोहन नहीं, बल्कि उसका उपयोग करना चाहिए। ऐसा करने पर ही यह धरती युगों-युगों तक हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हुई जीवन के विविध रूपों के साथ मुस्कराती रहेगी। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 15 प्रदूषित शहरों में भारत के लगभग 14 शहर हैं। प्रदूषण भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए। इंसानों ने अपने हाथों ही प्रकृति की नाक में दम करके अपने और अन्य प्राणी जाति का विनाश का सामान तैयार कर लिया है। बढ़ते प्रदूषण से जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ने की आशंका है। इंसान हर क्षेत्र में चाहे जितनी तरक्की कर ले, लेकिन शुद्ध आबोहवा के बिना इंसान अपना जीवन खुशहाली से नहीं जी सकता। धन दौलत से इंसान महंगा इलाज करवा सकता है, लेकिन पैसे से अच्छा स्वास्थ्य नहीं खरीद सकता। इस सच्चाई से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि इंसान प्रकृति के आगे अभी भी बौना है। अभी भी मौका है बढ़ते प्रदूषण को रोकने के उपाय किए जाएं, वरना वह दिन दूर नहीं, जब प्रदूषण से जीना दुश्वार हो जाएगा। बेहतर होता लेखक इससे निपटने का कोई उपाय भी बताते। raju09023693142@yahoo.com

सेना के प्रति सम्मान बढ़ा

जिस तरह हाल ही में सर्जिकल स्ट्राइक के सार्वजनिक हुए वीडियो को कांग्रेस और वामपंथी दलों के द्वारा राजनीतिक अमलीजामा पहनाने की कोशिश की जा रही है, वह बेहद निंदनीय है। 2014 में सत्ता पर काबिज हुई मोदी सरकार द्वारा सैनिकों की शहादत का बदला लेने के लिए 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया तब इससे बौखलाए वामदल और कांग्रेस ने सबूत सार्वजनिक करने के लिए कहा था, लेकिन अब सबूत सामने है तो भी अपना अलग राग अलाप रहे हैं। पिंटू सक्सेना, दिल्ली

अंगुलियां तो हमारी जलीं

आंदोलन के गर्भ से पैदा हुई पार्टी जब दिल्ली की राजनीति में उतरी तो उसे जरा भी अंदेशा नहीं रहा होगा कि दिल्ली की दाल इतनी आसानी से गल जाएगी। सत्ता में आने से पहले न तो आप ने, न ही चुनने वालों ने सोचा होगा कि वो शतरंज के मोहरे भर होंगे, चालें तो ऊपर वालों की होंगी। दिल्ली राज्य नहीं राजधानी है, तो फिर कैसी सरकार और कैसी सत्ता? दिल्ली के साथ हुई दिल्लगी लोगों को तब पता चली होगी जब अदालतों ने आईने दिखाए। खुमारी से जगी दिल्ली, बोझिल आंखों से पूछ रही है कि वह कहां गया जिसे उन्होंने चुना था? इस नायाब तंत्र-लोक में अगर दिल्ली को वैसे ही चलना था तो करोड़ो के वारे-न्यारे, ये लोकतंत्र के झूठे ताम-झाम किसके लिए? सियासत की आग में रोटी चाहे किसी की पकी या किसी की दाल गली हो, अंगुलियां तो हमारी जली हैं \mkmishra|z\\@yahoo.in

गरीबी के कुचक्र से निकलता भारत

भारत गरीबी से मुक्ति की ओर प्रगति कर रहा है और अगर इसी तेजी से प्रगति हुई तो 2030 तक हम यूनाइटेड नेशन के गरीबी मुक्त लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। फ्यूचर डेवलपमेंट की रिपोर्ट कहती हैकि भारत में हर मिनट 44 व्यक्ति गरीबी से ऊपर उठ रहा है जो कि दुनिया में सबसे जायदा है। यह अच्छा संकेत है। इसका श्रेय पिछले चार साल में सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए चलाई गई कई योजनाओं को जाता है। ब्रिटेन की एक रिपोर्ट के अनुसार जीडीपी ही विकास का आधार नहीं है लेकिन हमारे देश में जीडीपी के साथ-साथ गरीबी जैसे कुचक्र से भी देश बाहर निकलने की ओर अग्रसर है। नीरज झा, दिल्ली विश्वविद्यालय

साधु-संतों का जन्मदिवस

देशभर में कबीर जयंती धूमधाम से मनाई गई। सवाल उठता है कि क्या जयंती मना लेने मात्र से ही हमारे कर्तव्य की इतिश्री हो जाती है ? असल में संत-महात्मा अपनी आदर्शवादिता, व्यवहारिकता, कर्तव्यपरायणता व वाणी से समाज को जो सीख देते हैं, उसे जीवन में आत्मसात करना ही उनके प्रति सच्चा प्रेम है। आज भी समाज में चहुं ओर जात-पात, अंधश्रद्धा व सांप्रदायिक उन्माद चरम पर है। फिर साधु-संतों व देव विभूतियों के जन्मदिवस मनाने का औचित्य ही क्या है? सृष्टि का सच प्रत्यक्ष है। अंतकाल में अपना शरीर भी अपना साथ नहीं देता। वह भी पंचतत्व में ही विलीन हो जाता है। केवल और केवल व्यक्तिकृत कर्म ही साथ जाते हैं। तो फिर क्यों न संत-पथ पर चलकर सद् जीवन जिएं। उनकी उत्कृष्ट शिक्षाओं का अनुकरण करें। आप भी सुखी हों और औरों का जीवन भी सुखी बनाएं। इहलोक के साथ परलोक को भी सुधारें। neerajmaniktahla@rediffmail.com

अपनी लड़ाई खुद लड़े नारी

नारी शक्ति को अपनी सुरक्षा और हक की लड़ाई के लिए खुद आगे आना होगा। जब तक एक महिला दूसरी महिला का समर्थन नही करेगी तब तक महिलाओं पर हो रहे आपराधिक मामले पर रोक लगाना मुश्किल है। महिलाओं का डरकर चुप्पी साधना घातक साबित होगा। इससे अपराध करने वालों का हौसला बढ़ता है। इसलिए किसी भी अपराध के खिलाफ आवाज उठानी ही चाहिए। रवि पांडेय, फरीदाबाद

ट्वीट-ट्वीट

अपराधियों के एनकाउंटर पर उनके मानवाधिकारों को लेकर मामला बड़ी अदालत तक पहुंच जाता है, लेकिन अपराधियों की गोली से शहीद और घायल होने वाले पुलिसकर्मियों के लिए हमारी आंख नम तक नहीं होती।
अमिताभ अग्निहोत्री@Aamitabh2

केरल में समंदर से प्लास्टिक निकालकर और भी बेहतर सड़कें बनाई जा रही हैं। मछुआरे अब तक अरब सागर से 25 टन प्लास्टिक निकाल चुके हैं। महाराष्ट्र को भी यह प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन सड़क ठेकेदारों की आपत्तियों के चलते वहां यह सिरे नहीं चढ़ पाया।
नेविन जॉन@nevinjl

आरटीआइ से मिली जानकारी के अनुसार केजरीवाल सरकार ने पिछले 3 सालों में 17,115 पेड़ों को काटने की अनुमति दी और एक भी पेड़ काटने के प्रस्ताव को खारिज नहीं किया।
कपिल मिश्रा@KapilMishra_IND

बुराड़ी की कथित सामूहिक पारिवारिक आत्महत्याओं के पीछे की कथित मोक्ष कामना प्रमाण है कि आदिवासी ही नहीं नितांत शहरी, शिक्षित, संपन्न, मध्यवर्गीय चेतना भी कितनी विवेकहीन, अंधविश्वासी, तंत्र-मंत्र के सम्मोहन में फंसी आत्मघाती हो सकती है। 21वीं सदी की दिल्ली में 15वीं सदी में जीते लोग।
राहुल देव@rahuldev2

जनपथ

डॉलर ने दी पटखनी चढ़ि छाती पर बैठ,
चीं चीं चीं चिल्लाय के गया रुपैया ऐंठ।
गया रुपैया ऐंठ लिए अब छत्तिस सीना,
घूमे मुंह लटकाय रहा है पोंछ पसीना।
अपना हिंदुस्तान किए बस टाइट कॉलर,
रहा हमें लतियाय ट्रंप का हौव्वा डॉलर।
– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 28 अंक 349